www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 257 | जौनपुर गुरूवार, 07 मई 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

ओडिशा भारत के पूर्वी हिस्से को शक्ति प्रदान करने के लिए तैयारः सीएम माझी

अहमदाबाद, (एजेंसी)। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अहमदाबाद में ओडिशा इन्वेस्टर्स मीट (ओडिशा निवेशक सम्मेलन) में हिस्सा लिया। यह सम्मेलन पूर्वोदय की परिकल्पना के तहत अगली पीढ़ी के औद्योगिक विकास के लिए ओडिशा को एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में राज्य की राष्ट्रीय पहुंच में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय संस्कृति पत्रिका मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ष्गुजरात ने भारत के पश्चिमी हिस्से को शक्ति प्रदान की है। ओडिशा अब भारत के पूर्वी हिस्से को शक्ति प्रदान करने के लिए तैयार है, जो विकास की अगली सीमा तक व्यापकता, गति और रणनीतिक पहुंच प्रदान करता है। भविष्य की ओर देख रहे उद्योगों के लिए ओडिशा न केवल एक अवसर है, बल्कि एक दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धी लाभ भी है।ष्मुख्यमंत्री की गुजरात यात्रा के पहले दिन उद्योग जगत के नेताओं, व्यापार संघों और संस्थागत हितधारकों की मजबूत भागीदारी देखी गई, जो ओडिशा के विकसित होते औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। सीएम मोहन चरण माझी ने 500 से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों की सभा को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया।

कर्नाटक सीएम श्रृंगेरी विधानसभा क्षेत्र में वोटों की पुनर्गणना में मत चोरी का आरोप लगाया

बेंगलुरु, (एजेंसी)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को श्रृंगेरी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी धांधली के गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि डाक मतपत्रों के प्रबंधन और मतगणना में श्आपराधिक साजिशश रची गई थी। श्रृंगेरी विधानसभा क्षेत्र में 2023 के विधानसभा चुनावों के डाक मतपत्रों का पुनर्सत्यापन और पुनर्गणना उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद की गई थी। पुनर्गणना के बाद, भाजपा उम्मीदवार ने मौजूदा कांग्रेस विधायक को हरा दिया।अपने आधिकारिक आवास श्कृष्णाश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार टीडी राजेगौड़ा ने मूल रूप से 201 वोटों के अंतर से 201 वोटों से जीत हासिल की थी, उन्हें 59,171 वोट मिले थे जबकि भाजपा उम्मीदवार डीएन जीवराज को 58,970 वोट मिले थे। उन्होंने बताया कि राजेगौड़ा को मिले कुल वोटों में से 58,602 वोट ईवीएम के माध्यम से और 569 वोट डाक मतपत्रों के माध्यम से आए, जबकि जीवराज को 58,278 ईवीएम वोट और 692 डाक मतपत्र मिले।उन्होंने कहा कि उस समय इन सभी वोटों को वैध घोषित कर दिया गया था और चुनाव अधिकारियों एवं मतगणना एजेंटों ने परिणामों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। हालांकि, अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए।

रेलवे को बड़ी सौगात- 23,437 करोड़ की तीन परियोजनाएं मंजूर, विकास को मिलेगी रफ्तार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रेल मंत्रालय की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिनकी कुल लागत लगभग 23,437 करोड़ रुपये है। पीएम मोदी का कहना है कि इससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ–साथ आर्थिक विकास को भी तेज रफ्तार मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, आर्थिक विकास को गति!" उन्होंने बताया, "मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं के लिए कैबिनेट की मंजूरी से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और परिचालन क्षमता में सुधार होगा। इससे पूरे देश में प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच भी बेहतर होगी।" दरअसल, मंगलवार को सरकार ने रेलवे की तीन बड़ी मल्टी–ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन प्रोजेक्ट्स की कुल लागत करीब 23,437 करोड़ रुपये है और इन्हें 2030–31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन योजनाओं के तहत भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 901 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। इन तीन अहम परियोजनाओं में नागदा–मथुरा थर्ड और फोर्थ लाइन, गुंटकलदृवाडी थर्ड और फोर्थ लाइन और बुरहवालदृसीतापुर थर्ड और फोर्थ लाइन शामिल हैं। इन लाइनों के बढ़ने से ट्रेनों की आवाजाही आसान होगी, देरी कम होगी और रेलवे की सेवा ज्यादा भरोसेमंद बनेगी। ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों को कवर करेंगे। इससे करीब 4,000 से ज्यादा गांवों (लगभग 83 लाख आबादी) को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। सरकार का कहना है कि ये योजनाएं पीएम–गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई हैं।

नीतीश कुमार ने पटना में जदयू कार्यालय का अचानक दौरा किया

पटना, (एजेंसी)। बिहार में प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार से पहले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार शाम को पटना स्थित जनता दल (यूनाइटेड) (जदयू) के मुख्यालय, कर्पूरी भवन का अचानक दौरा किया। पार्टी सूत्रों के अनुसार, नेताओं को उनके आधिकारिक आवास से निकलने के बाद ही उनके आने की जानकारी मिली। उनके आगमन पर कार्यालय में उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दौरे के दौरान, नीतीश कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की और अनौपचारिक चर्चा की।वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक चौधरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। जदयू एमएलसी संजय गांधी ने कहा कि इस तरह के दौरे असामान्य नहीं हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वयं पार्टी कार्यालय के विकास की देखरेख की है और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए अक्सर आते रहते हैं। गांधी ने कहा कि पहले वे मुख्यमंत्री

के रूप में आते थेय आज वे पार्टी नेता के रूप में कार्यकर्ताओं से जुड़ने आए हैं। हमें पहले से सूचित नहीं किया गया था। जब भी वे आते हैं, वे हर छोटी–बड़ी बात की समीक्षा करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके द्वारा स्थापित व्यवस्थाएं ठीक से काम कर रही हैं।उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार संगठनात्मक रणनीतियों पर चर्चा करने और पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से नियमित रूप से बातचीत करते हैं।

अमित शाह ने शपथ ग्रहण समारोह और नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर रणनीति पर चर्चा करेंगे

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार शाम पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। वह बिहार में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद सीधे बंगाल के लिए रवाना होंगे। सूत्रों के मुताबिक, अमित

शाह अपने दौरे के दौरान पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। 8 मई को होने वाली विधायक दल की बैठक से पहले वे शपथ ग्रहण समारोह और नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर रणनीति पर चर्चा करेंगे। इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसी में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के स्वरूप को अंतिम रूप दिया जा सकता है। भाजपा ने अमित शाह को पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उनके साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को केंद्रीय सह–पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसकी जानकारी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी। गौरतलब है कि इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार सरकार बनाने का रास्ता साफ किया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, 294 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 207 सीटें मिली हैं जबकि टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई। इसके अलावा कांग्रेस को 2 और सीपीआई (एम) को 1 सीट मिली है। चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह की भूमिका बेहद अहम रही।

हर जरूरतमंद का बनवाएं आयुष्मान कार्ड : योगी आदित्यनाथ

गोरखपुर, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों से उन्होंने आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा और आश्वस्त किया कि सरकार इलाज कराने में भरपूर मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जरूरतमंद, पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले। उनके पास जाकर उनकी समस्याएं सुनीं। उनके प्रार्थना पत्रों का अवलोकन कर समस्या, शिकायत का संज्ञान लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि वे परेशान न हों, सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है। उन्होंने अलग–अलग मामलों के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित करते हुए निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिप्रद निस्तारण होना चाहिए। जनता दर्शन में हर बार की तरह बुधवार को भी कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे। मुख्यमंत्री ने उनसे आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा, साथ ही भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। अस्पताल का एस्टीमेट मिलते ही विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता की हर पीड़ा का निवारण सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। जनता दर्शन में कुछ महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी आए थे। मुख्यमंत्री ने बच्चों को प्यार किया और उन्हें आशीर्वाद के साथ चॉकलेट दी। इस दौरान उन्होंने एक महिला के साथ आए दो बच्चों से हंसी–ठिठोली भी की और उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया।

असम में 11 मई के बाद बनेगी नई सरकार : हिमंता बिस्वा सरमा

दिसपुर, (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि राज्य में नई भाजपा–नीत सरकार का गठन और शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद होगा, जब संवैधानिक और संगठनात्मक औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने कहा कि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के नतीजों की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद उन्होंने लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप अपने मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंप दिया। सीएम सरमा ने कहा, ष्चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर नतीजों की घोषणा कर दी है और राज्यपाल को अधिसूचना सौंप दी है। इसके तुरंत बाद, मैंने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया और वर्तमान असम विधानसभा को भंग करने की भी सिफारिश की।ष उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने दोनों सिफारिशें स्वीकार कर लीं और निवर्तमान मंत्रालय से तब तक कार्यवाहक सरकार के रूप में काम जारी रखने को कहा, जब तक कि नया मंत्रालय कार्यभार नहीं संभाल लेता। उन्होंने कहा, ष्इस संक्रमण काल घ्के दौरान, जब तक नई सरकार नहीं बन जाती, हम एक कार्यवाहक सरकार के रूप में काम करते रहेंगे। हालांकि, सीएम सरमा ने संकेत दिया कि शपथ ग्रहण समारोह 11 मई से पहले नहीं होगा। उन्होंने कहा, ष्मैंने 12 मई के बारे में चर्चाएं सुनी हैं, हालांकि मैं आधिकारिक तौर पर तारीख की पुष्टि नहीं कर सकता। मैं यह कह सकता हूं कि नई सरकार का गठन और शपथ ग्रहण 11 मई के बाद ही होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा विधायक दल की एक बैठक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी, जिन्हें केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक दल अपने नेता का चुनाव करेगा, जिसके बाद एनडीए की एक बैठक औपचारिक रूप से उस उम्मीदवार का समर्थन करेगी और फिर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। सीएम सरमा ने आगे कहा, ष्इसके बाद राज्यपाल चुने हुए नेता को मंत्रालय बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे।

पश्चिम बंगाल हिंसा पर ज्ञानेश कुमार का कड़ा रुख, तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए

कोलकाता, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। कई जगहों से हिंसा, झड़प और तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं। इसी को देखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि जो भी लोग हिंसा भड़काने या तोड़फोड़ में शामिल हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सीईसी ने राज्य के बड़े अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव, डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रमुख महानिदेशकों (डीजी) को अलर्ट रहने को कहा है। साथ ही सभी जिलों के डीएम, एसपी और पुलिस अधिकारियों को लगातार गश्त करने का आदेश दिया गया है ताकि हालात काबू में रहें। चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि चुनाव के बाद किसी भी

तरह की हिंसा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंसा भड़काने और तोड़फोड़ करने वाले तुरंत गिरफ्तार होंगे। मंगलवार को कोलकाता के न्यूटाउन इलाके में भाजपा के एक कार्यकर्ता की पीट–पीटकर हत्या कर दी गई। इस कार्यकर्ता का नाम मधु मंडल बताया जा रहा है। आरोप है कि इस घटना में टीएमसी समर्थकों का हाथ है। इस हत्या के बाद परिवार और स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा फैल गया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। सिर्फ न्यूटाउन ही नहीं, बल्कि राज्य के कई और इलाकों से भी हिंसा की खबरें आई हैं।

भाजपा ने लोकतंत्र का अपहरण कर उसे नष्ट कर दिया है : अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर लोकतंत्र का अपहरण करने और उसे नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने पंजाब के आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की उपस्थिति में कहा कि राज्य में चार साल सत्ता में रहने

के बाद भी सत्ता समर्थक रुझान दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। उन्होंने वोटों की हेराफेरी और जोड़–तोड़, श्चोरीश की गई राज्यसभा सीटों और राज्य के हकों से वंचित करने के मामले में भाजपा पर तीखा हमला भी किया।राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के बाद नई दिल्ली स्थित पंजाब के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास कपूरथला हाउस पहुंचे विधायकों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार बने चार साल हो गए हैं और चुनाव में अब 10 महीने बचे हैं। चुनाव से ठीक एक साल पहले सरकार की तारीफ करना बहुत कम देखने को मिलता है। आमतौर पर चार साल बाद लोग कहते हैं कि सत्ता विरोधी लहर जोरों पर है। लेकिन पंजाब में आप किसी भी गांव या मोहल्ले में जाइए, आज वहां सत्ता विरोधी लहर नहीं हैय बल्कि सत्ता समर्थक लहर है। लोग खुलकर और दिल से पंजाब सरकार की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है।लोकतंत्र पर चिंता जताते हुए आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि पूरे देश में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। भाजपा ने लोकतंत्र का अपहरण कर उसे नष्ट कर दिया है। चुनाव जीतने से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।

राहुल गांधी की बात न मानकर ममता ने की गलती : संजय राउत

मुंबई, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने तृणमूल कांग्रेस की हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सलाह को नजरअंदाज करके बड़ी गलती की। उनके मुताबिक, यदि उस सलाह पर अमल किया जाता, तो चुनावी नतीजे अलग हो सकते थे।मीडिया से बातचीत में राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही चुनावों को लेकर कुछ गंभीर मुद्दे उठाए थे, जिन्हें पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। उन्होंने दावा किया कि अगर उन बातों को ध्यान में रखा जाता, तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो सकती थी। राउत ने राहुल गांधी को "दूरदर्शी नेता" बताते हुए कहा कि उन्होंने जो आशंकाएं जताई थीं, वे अब सच साबित होती नजर आ रही हैं।संजय राउत ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यह केवल लोकतांत्रिक जीत नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ प्रक्रियात्मक मुद्दे भी हो सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए, जिसका असर चुनाव परिणामों पर पड़ा। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने इस बार निर्णायक बहुमत हासिल करते हुए पहली बार सरकार बनाने की स्थिति बनाई है। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस के लगभग 15 साल लंबे शासन का अंत हो गया है। यह बदलाव राज्य की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा को जन्म दिया है।राउत ने कहा कि भले ही पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में विपक्षी दलों को झटका लगा हो, लेकिन ष्छक्प। गठबंधन का भविष्य अभी भी मजबूत है। उन्होंने विश्वास जताया कि विपक्षी दल एकजुट होकर आगे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी हार किसी भी गठबंधन के अंत का संकेत नहीं होती, बल्कि यह आत्ममंथन और सुधार का अवसर प्रदान करती है।अपने बयान में राउत ने तमिलनाडु का भी उल्लेख किया और वहां के राजनीतिक घटनाक्रम को भी विपक्ष के लिए चुनौती बताया।

संपादकीय

जन कल्याण का रास्ता टिकाऊ नहीं

भारत में जन कल्याण का जो रास्ता चुना गया है, वह टिकाऊ नहीं है। हर वर्ष पिछले साल की तुलना में औसतन अधिक कर्ज लेने के बावजूद सरकारें नकदी हस्तातंरण की योजनाओं को सुगमता से नहीं चला पा रही हैं। बृहत–मुंबई महानगर पालिका के रिटायर शिक्षक का पेंशन भुगतान ना होने के बचाव में सरकार ने खजाने में पैसा ना होने का तर्क दिया। तो उससे नाराज बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के पास अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, तो उसे लड़की बहन योजना रोक देनी चाहिए। इस योजना के तहत राज्य की डेढ़ करोड़ महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं। खुद राज्य के मंत्री ऐसे बयान दे चुके हैं कि इस योजना से राजकोष पर पड़े भारी बोझ के कारण तमाम विभागों के बजट प्रभावित हुए हैं। इस बीच हरियाणा में अस्पतालों के संघ ने संबंधित अधिकारी को पत्र लिख कर कहा है कि 20 अप्रैल तक उनके बकाये का भुगतान नहीं हुआ, तो वे आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को भर्ती करना बंद कर देंगे। पत्र में ध्यान दिलाया गया है कि अस्पतालों का 400 करोड़ रुपये से अधिक बकाया सरकार पर है। आयुष्मान भारत के बारे में ऐसी शिकायतें कई अन्य राज्यों से भी आई हैं। ये खबरें बताती हैं कि भारत में जन कल्याण का जो रास्ता चुना गया है, वह टिकाऊ नहीं है। हर वर्ष पिछले साल की तुलना में औसतन अधिक कर्ज लेने के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारें नकदी हस्तातंरण की योजनाओं को सुगमता से नहीं चला पा रही हैं। और ऐसा होना अस्वाभाविक नहीं है। यह मूलभूत सिद्धांत है कि कोई अर्थव्यवस्था उत्पादक निवेश और पूंजी निर्माण पर टिकी नहीं है, तो वह उपभोग उन्मुख जन कल्याण को सुनिश्चित नहीं कर सकती। ऋण लेना अपने आप में समस्या नहीं है, बशर्ते उसका उपयोग उत्पादन बढ़ाने या टिकाऊ संपत्ति खड़ी करने में हो रहा हो। इन दोनों प्रक्रियाओं से मांग पैदा होती है, जिससे स्वतरू उपभोग बढ़ता है। इस क्रम में सरकार का कर राजस्व बढ़ता है, जिससे वह टिकाऊ जन– कल्याण योजनाओं को चलाने की बेहतर स्थिति में होती है। मगर अपने यहां उलटी राह चुनी गई है। इस बीच चुनावी राजनीति में वोट खरीदने की बढ़ी प्रवृत्ति ने स्थिति ओर बिगाड़ दी है। उसका परिणाम महाराष्ट्र और हरियाणा जैसी स्थितियां हैं।

छत्तीसगढ़ की जड़ी-बूटियों से महकेगा नारी शक्ति का स्वावलंबन

धनंजय

छत्तीसगढ़ के वनांचल की गोद में छिपी अमूल्य औषधि संपदा अब केवल स्वास्थ्य का आधार नहीं, बल्कि प्रदेश की नारी शक्ति के आर्थिक स्वावलंबन का नया अध्याय बन रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सुशासन की जिस परिकल्पना को साकार कर रही है, उसे वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड धरातल पर उतार रहा है। गिलोय, कालमेघ, बहेड़ा, सफेद मूसली, जंगली हल्दी, गुड़मार, अश्वगंधा, और शतावरी जैसी महत्वपूर्ण औषधीय वनस्पतियों से अर्क और उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक पहचान वनांचल में बिखरे पारंपरिक ज्ञान को महज एक स्मृति न रहने देने के संकल्प के साथ बोर्ड ने इसे वैज्ञानिक पद्धति से जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके तहत उन स्थानीय वैद्यों और जानकारों का चिन्हांकन शुरू किया गया है, जिनके पास असाध्य रोगों के उपचार का अद्भुत ज्ञान है। बोर्ड का प्रयास इन महिलाओं को एक उचित मंच प्रदान करना है, ताकि उनकी विशेषज्ञता का लाभ समाज को मिले और वे स्वयं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर सकें। यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उस विरासत का सम्मान है जिसे ग्रामीण महिलाओं ने सदियों से सहेजकर रखा है। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक जड़ी–बूटी और जनजातीय ज्ञान को अब आधुनिक विज्ञान के माध्यम से नई पहचान मिल रही है। राज्य के वनों में छिपे औषधीय खजाने को वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित कर, उसे आजीविका के साधन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उद्यमिता की नई उड़ान आर्थिक मोर्चे पर सबसे बड़ा बदलाव तब दिखाई दे रहा है, जब जड़ी–बूटियों का संग्रहण करने वाली महिलाएं अब संग्राहक से आगे बढ़कर निर्माता की भूमिका में नजर आ रही हैं। बोर्ड के दिशा–निर्देशों के अनुरूप, महिला स्व–सहायता समूहों को औषधि प्रसंस्करण के उन्नत गुर सिखाए जा रहे हैं। यह पहल न केवल औषधीय पौधों का संरक्षण कर रही है, बल्कि वनवासियों और लघु वन उपज संग्राहकों की आय में वृद्धि करके उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। छत्तीसगढ़ में 1500 से अधिक सक्रिय वैद्यों के ज्ञान को सहेजने और जड़ी–बूटियों के विपणन के लिए छत्तीसगढ़ जनजातीय स्थानीय स्वास्थ्य परंपराएं और औषधीय पादप बोर्ड सक्रिय रूप से काम कर रहा है। यह संस्था हर्बल उत्पादों की खेती, मूल्य संवर्धन, और मार्केटिंग में तकनीकी सहायता और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करती है। छत्तीसगढ़ में जड़ी–बूटी मूल्य संवर्धन एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से राज्य के समृद्ध वन संसाधनों को वैज्ञानिक तरीके से संसाधित करके उनके आर्थिक मूल्य को बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार शछत्तीसगढ़ हर्बल्सश ब्रांड के तहत इन उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। जब ये महिलाएं वनों से प्राप्त कच्ची सामग्री को साफ कर, सुखाकर उसे चूर्ण, अर्क या तेल के रूप में परिवर्तित करती हैं, तो उत्पाद की कीमत और गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। इस मूल्य संवर्धन का सीधा आर्थिक लाभ उनके बैंक खातों तक पहुँच रहा है, जिससे बिचौलियों का वर्चस्व पूरी तरह समाप्त हो गया है। गिलोय, कालमेघ, बहेड़ा, सफेद मूसली, जंगली हल्दी, गुड़मार, अश्वगंधा, और शतावरी जैसी महत्वपूर्ण औषधीय वनस्पतियों से अर्क और उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। 65 से अधिक लघु वन उपज प्रजातियों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (रूस्क्क) पर खरीदी और उनका प्रसंस्करण किया जा रहा है। यह पहल छत्तीसगढ़ को एक प्रमुख हर्बल स्टेट के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो परंपरा और आधुनिक तकनीक का संगम है। छत्तीसगढ़, जिसे शबूटिगढ़श भी कहा जाता है, अपने घने जंगलों, विशेषकर बस्तर में 160 से अधिक प्रकार की दुर्लभ जड़ी–बूटियों का प्राकृतिक खजाना है। यहाँ की मिट्टी में अश्वगंधा, सर्पगंधा, गोक्षुरा (गोखरू), कुटकी और तिखुर जैसी औषधियां पाई जाती हैं, जो स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं । बाजार की चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए बोर्ड ने विपणन तंत्र को पारदर्शी बनाया है। प्रदेश के छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड को सशक्त करने के लिए प्रदर्शनियों और रिटेल आउटलेट्स के माध्यम से इन उत्पादों को सीधे शहरी उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के व्होकल फार लोकल और मुख्यमंत्री के लखपति दीदी अभियान को सफल बनाने में यह रणनीति संजीवनी का कार्य कर रही है। नर्सरी प्रबंधन और स्थानीय रोजगार जड़ी बूटियों को किचिन गार्डन, होम गार्डन में खिड़की, बालकनी, टेरिस पर गमलों, या अन्य कंटेनरों में कभी भी उगाया जा सकता है। कंटेनर गार्डनिंग या ग्रो बैग में जड़ी–बूटियां उगाने का एक फायदा यह भी है कि जड़ी बूटी को उसकी जरूरत के आधार पर मिट्टी, पोषक तत्व, सूर्य प्रकाश और नमी के स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है ।

बंगाल में निर्ममता की हार, तुष्टिकरण पर प्रहार और विकास की बयार

प्रेम

पश्चिम बंगाल के जनादेश ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि जनता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्णायक, प्रभावी और परिणाम देने वाले नेतृत्व पर अडिग विश्वास रखती है। यह भरोसा किसी भावनात्मक लहर का परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों से दिख रहे सुशासन, पारदर्शिता और निरंतर विकास की ठोस बुनियाद पर खड़ा है। यह केवल एक चुनावी परिणाम नहीं, बल्कि बंगाल की जनता के भीतर वर्षों से पनप रहे आक्रोश, पीड़ा और बदलाव की आकांक्षा का सशक्त विस्फोट है। इस जनादेश में साफ दिखता है कि जनता ने भय की राजनीति को नकारते हुए भरोसे को अपनाया, तुष्टिकरण को ठुकराकर विकास को चुना और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होकर सुशासन को प्राथमिकता दी। बंगाल में यह जीत वास्तव में जनता की जीत है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में चल रहे टोलाबाजी, सिंडिकेट राज, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और खुले तुष्टिकरण के खिलाफ जनता लंबे समय से सड़कों पर थी। हर वर्ग, चाहे वह किसान हो, युवा हो, महिला हो या व्यापारी, सबने इस व्यवस्था के खिलाफ मन बना लिया था। पिछले वर्षों में पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिन्दू समाज के साथ भेदभाव हुआ, वह किसी से छिपा नहीं है। तुष्टिकरण की राजनीति ने सामाजिक संतुलन को बिगाड़ा और अवैध घुसपैठ को प्रोत्साहन देकर राज्य की पहचान और सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़े कर दिए गए। हालात ऐसे बन गए थे कि कई इलाकों में हिन्दू समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया। चुनाव के समय उन्हें वोट डालने तक से रोका गया, डराया–धमकाया गया। यह लोकतंत्र का अपमान था, लेकिन इस बार जनता ने इन सबका जवाब दिया है। ममता बनर्जी की हताशा चुनाव से पहले ही दिखने लगी थी। एक भ्रष्ट निजी कंपनी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना, मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की उपस्थिति का विरोध करना, ये सभी कदम इस बात के संकेत थे कि उन्हें अपनी हार का अंदाजा हो चुका था। लेकिन लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है और जनता ने अपना फैसला स्पष्ट रूप से सुना दिया। यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि देश की जनता आज भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व पर अटूट विश्वास रखती है। पिछले 12 वर्षों में केंद्र में भाजपा की सरकार ने जिस तरह से विकास और सुशासन का मॉडल प्रस्तुत किया है, उसका असर हर राज्य में दिख रहा है। जहां–जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां न केवल विकास हुआ है बल्कि जनता ने बार–बार उस पर मुहर लगाई है। असम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनना और वह भी पहले से अधिक, लगभग तीन–चौथाई बहुमत के साथ, यह बताता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्य सरकारों ने विकास के नए मानक स्थापित किए हैं। असम में बुनियादी ढांचे से लेकर कानून–व्यवस्था तक हर क्षेत्र में सुधार हुआ है, जिसका परिणाम जनता के विश्वास के रूप में सामने आया है। इन विधानसभा चुनावों में विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आया। राहुल गांधी एक बार फिर इस चुनाव में असफल नेता के रूप में सामने आए हैं। वह न तो इंडी गठबंधन को एकजुट रख पाए और न ही जनता के बीच कोई विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत कर पाए। चुनाव परिणामों के समय उनका विदेश में होना यह दर्शाता है कि वह इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेने के लिए तैयार ही नहीं हैं। इंडी गठबंधन अब केवल नाम का गठबंधन रह गया है, जिसका भविष्य अंधकारमय दिखता है। तमिलनाडु में वर्षों से जो लोग सनातन संस्कृति का अपमान करते आए, जिन्होंने हिन्दू आस्थाओं को निशाना बनाया, दीपम जैसे धार्मिक आयोजनों में बाधाएं डालीं और धर्म–भाषा के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश की। जनता ने उन्हें भी करारा जवाब दिया है। सनातन संस्कृति की तुलना डेंगू–मलेरिया जैसी बीमारियों से करने वाली मानसिकता को जनता ने नकार दिया है। यह बदलाव धीरे–धीरे ही सही, लेकिन स्थायी रूप से उभर रहा है। पुडुचेरी में भी भाजपा के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। भले ही यह प्रतिशत में कम दिखे, लेकिन यह संकेत स्पष्ट है कि दक्षिण भारत में भी भाजपा अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी वैचारिक बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। केरल में भी भाजपा का आधार लगातार मजबूत हो रहा है। भले ही अभी वहां सत्ता तक पहुंचने में समय लगे, लेकिन जनता के बीच वैचारिक परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा है। यह दर्शाता है कि देश का हर कोना अब विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति की ओर बढ़ रहा है। बंगाल की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं का संघर्ष और बलिदान छिपा हुआ है। पिछले कई वर्षों में, खासकर पिछले विधानसभा चुनाव के बाद, भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिस तरह की हिंसा और उत्पीड़न का सामना किया, वह अभूतपूर्व था। हजारों कार्यकर्ताओं को बेघर होना पड़ा, कईयों

के घरों में आग लगा दी गई, दुकानों को लूट लिया गया, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए और कई कार्यकर्ताओं ने अपनी जान तक गंवाई। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों द्वारा किए गए इन अत्याचारों के बावजूद भाजपा कार्यकर्ता डटे रहे। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि और मजबूती से संघर्ष किया। यह संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि विचारधारा और लोकतंत्र की रक्षा का संघर्ष था। आज जब बंगाल में कमल खिला है, तो यह केवल एक पार्टी की जीत नहीं, बल्कि उन सभी कार्यकर्ताओं के बलिदान का परिणाम है, जिन्होंने अपने खून–पसीने से इस जमीन को सींचा। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर यह जीत विशेष महत्व रखती है। यही वह भूमि है जहां से वैकल्पिक राजनीति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव रखी गई थी। आज उसी धरती पर भाजपा का परचम लहराना, उस विचारधारा की जीत है जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सर्वोपरि मानती है। यह जनादेश लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और सबसे बढ़कर बंगाल की जनता की जीत है। यह संदेश साफ है, जो सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती, जो भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण में डूबी होती है, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जो सरकार विकास, सुशासन और विश्वास के साथ आगे बढ़ती है, जनता उसे बार–बार अपना समर्थन देती है। यह केवल शुरुआत है। आने वाले समय में देश की राजनीति और अधिक स्पष्ट होगी, एक तरफ विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति होगी और दूसरी तरफ अवसरवाद और तुष्टिकरण की। जनता ने अपना रास्ता चुन लिया है, और यह रास्ता परिवर्तन का है, प्रगति का है और एक मजबूत भारत के निर्माण का है।

बंगाल विजय: संघ की जमीनी साधना शांति से शक्ति तक

ललित

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ऐतिहासिक, अद्भुत, अविस्मरणीय एवं करिश्माई जीत के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (संघ) की बहुत बड़ी भूमिका रही है। निश्चिततौर पर इस शानदार जीत के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह मुख्य भूमिका में हैं। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी की मजबूत चुनौती के सामने भाजपा की जीत के लिए संघ लंबे समय से मेहनत कर रही थी और उसकी वह मेहनत ही जीत का सशक्त माध्यम बनी है। पश्चिम बंगाल में लगातार चल रही हिन्दू विरोधी गतिविधियों एवं मुसलमानों के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए संघ ने इस चुनाव के मद्देनजर बहुत पहले से ही कमर कस ली थी, संघ ने पश्चिम बंगाल में 1.75 लाख से अधिक छोटी–बड़ी बैठकें आयोजित कीं। पिछले 15 सालों में संघ ने पश्चिम बंगाल में तेजी से विस्तार किया है और एक मजबूत 'हिंदू वोट बैंक' तैयार किया है। पश्चिम बंगाल में पिछले 15 वर्षों में संघ की शाखाओं की संख्या 900 से बढ़कर 5,000 तक पहुंच गई है। संघ के स्वयंसेवकों ने पश्चिम बंगाल में घर–घर जाकर 'बंग बचाओ' इस थीम पर 'मतदाता जागरूकता अभियान' चलाया। संघ की माइक्रो प्लानिंग ने बंगाल में भाजपा को ऐतिहासिक बढ़त दिलाई और सत्ता परिवर्तन का माध्यम बनी। पश्चिम बंगाल चुनाव भाजपा के लिए एक ऐतिहासिक 'मील का पत्थर' और ऐतिहासिक सफलता साबित हुआ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि राजनीति केवल बड़े मंचों, विशाल रैलियों और जोरदार नारों से तय नहीं होती। कई बार असली लड़ाई उन स्तरों पर लड़ी जाती है, जहां न कैमरे पहुंचते हैं और न ही जमीनी प्रयास सुर्खियां बनती हैं। इस बार के चुनाव में एक ऐसी ही खामोश रणनीति कारगर साबित हुई है। जहां एक ओर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का आक्रामक चुनाव प्रचार केंद्र में रहा, वहीं दूसरी ओर संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं ने अपेक्षाकृत शांत रहकर 'निःशब्द विप्लव' या 'मूक क्रांति' को अंजाम देते हुए जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने पर ध्यान दिया। बंगाल की अस्मिता, विकास और सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दों को आधार बनाकर जनजागरण अभियान चलाया गया। इस दौरान महिला, युवा, प्रबुद्ध वर्ग, किसान, श्रमिक और अनुसूचित जाति–जनजाति समुदायों तक अलग–अलग तरीकों से पहुंचने की कोशिश की गई। निश्चिततौर पर पश्चिम बंगाल की राजनीति ने वर्ष 2026 में जो ऐतिहासिक करवट ली, वह केवल सत्ता परिवर्तन की घटना नहीं है, बल्कि एक गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक परिवर्तन का संकेत भी है। लंबे समय तक वामपंथी प्रभाव और उसके बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व रहा, लेकिन इस बार जनमत ने जिस प्रकार से भाजपा के पक्ष में निर्णायक रूप से झुकाव दिखाया, उसने स्थापित राजनीतिक धारणाओं को चुनौती दी है। इस परिवर्तन के मूल में जो शक्ति को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी रही है तो वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने एक अदृश्य लेकिन अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभाई है। यह विजय केवल चुनावी रणनीतियों का परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों से चल रहे संगठनात्मक परिश्रम, वैचारिक विस्तार और समाज के भीतर गहराई तक किए गए संवाद का परिणाम है। पश्चिम बंगाल में संघ का विस्तार किसी तात्कालिक राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित नहीं था, बल्कि यह एक दीर्घकालिक सामाजिक दृष्टि का हिस्सा था। पिछले डेढ़ दशक में संघ ने प्रांत में जिस प्रकार अपनी शाखाओं का विस्तार किया और समाज के विभिन्न वर्गों तक अपनी पहुंच बनाई, उसने एक मजबूत वैचारिक आधार तैयार किया। यह कार्य किसी प्रचार की तरह नहीं, बल्कि एक शांत सामाजिक प्रक्रिया एवं क्रांति की तरह हुआ, जिसने धीरे–धीरे जनमानस को प्रभावित किया। यही कारण है कि जब चुनाव का समय आया, तो एक पहले से तैयार मानसिकता भाजपा के पक्ष में खड़ी दिखाई दी। इस पूरे परिदृश्य में सरसंघचालक मोहन भागवत की रणनीतिक दृष्टि को भी विशेष रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए। उन्होंने बंगाल को केवल एक राजनीतिक इकाई के रूप में नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक भूमि के रूप में देखा, भारत की अस्मिता के रूप में देखा। जिसकी अपनी विशिष्ट पहचान और परंपराएं हैं। संघ के प्रयासों में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि उसने बंगाल की सांस्कृतिक चेतना को समझने और उससे जुड़ने का प्रयास किया। दुर्गा पूजा, काली पूजा और रामनवमी जैसे पर्वों को सामाजिक एकता और सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिससे एक व्यापक सामाजिक जुड़ाव स्थापित हुआ। इस प्रक्रिया में हिंदुत्व को किसी बाहरी विचारधारा के रूप में नहीं, बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक आत्मा के एक स्वाभाविक विस्तार के रूप में प्रस्तुत किया गया। लंबे समय तक यह धारणा बनी रही कि बंगाली अस्मिता और हिंदुत्व परस्पर विरोधी हैं, लेकिन इस चुनाव में यह धारणा काफी हद तक टूटती हुई दिखाई दी। "जय श्री राम" के साथ "जय मां काली" और "जय मां दुर्गा" जैसे नारों का समन्वय केवल राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक संदेश था, जिसने यह स्थापित किया कि क्षेत्रीय पहचान और व्यापक सांस्कृतिक विचारधारा के बीच कोई टकराव नहीं है। इस समन्वय ने मतदाताओं के भीतर एक नई प्रकार की आत्मजागरूकता उत्पन्न की, जहां वे केवल विकास या योजनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी पहचान, सुरक्षा और सांस्कृतिक गौरव के आधार पर भी निर्णय लेने लगे। चुनाव के दौरान जिस प्रकार से 'अस्तित्व' एवं 'अस्मिता' का विमर्श उभरा, उसने इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को एक नई दिशा दी। संघ और भाजपा ने इसे केवल एक चुनावी मुकाबले के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि एक वैचारिक संघर्ष के रूप में स्थापित किया, जिसमें पहचान और सम्मान के प्रश्न प्रमुख हो गए। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पर लगाए गए तुष्टिकरण के आरोपों ने इस विमर्श को और तीव्र किया, जिससे मतदाताओं के बीच एक स्पष्ट ध्रुवीकरण देखने को मिला। इस पूरे प्रक्रिया में संघ ने जमीनी स्तर पर संवाद स्थापित कर इस विचार को सामाजिक स्वीकृति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

एग्री स्टैक– भारत की डिजिटल कृषि क्रांति

डॉ. देवेश चतुर्वेदी

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। इस क्षेत्र में कुल श्रमशक्ति का लगभग 46 प्रतिशत हिस्सा जुटा हुआ है। पिछले दशक में सरकार की ओर से उत्पादनध्उत्पादकता बढ़ाने, फसलों के विविधीकरण, खेती की लागत में कमी लाने, कृषि उत्पादों की बेहतर कीमत अर्जित करने, जलवायु के अनुकूल ढालने और जोखिमों को कम करने की बहुआयामी रणनीति के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के ठोस प्रयास किए गए हैं। केन्द्र प्रायोजित या केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के जरिए किसानों को विभिन्न सेवाओं या लाभों की निर्बाध, पारदर्शी और कुशल आपूर्ति संघीय या राज्य स्तर की सरकार की प्राथमिकता है। कुल कृषि भूमि का स्वामित्व और उस भूमि पर बोई गई फसलों का इतिहास किसी भी योजना के लाभ के लिए किसी भी किसान (चाहे वह मालिक हो, पट्टेदार हो या फिर बटाईदार हो) की पात्रता के आकलन की जरूरी शर्त है। हालांकि, देश भर में भूमि से संबंधित प्रशासन में पायी जाने वाली व्यापक भिन्नताएं एक बड़ी चुनौती पेश करती हैं। स्वामित्व और बुवाई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को संकलित करने वाले एक मानकीकृत किसान डेटाबेस के महत्व एवं जरूरत को पहचानते हुए, सरकार ने वर्ष 2024 में डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत की। किसानों के इस डेटाबेस को मजबूत सहमति तंत्र के साथ गतिशील रूप से अद्यतन किया जाता है। एग्री स्टैक, इस डिजिटल कृषि मिशन का एक प्रमुख स्तंभ है। यह अब इस मिशन के एक मौन लेकिन सशक्त परिवर्तनकारी स्तंभ के रूप में उभर रहा है। इसमें तीन विवरणी (रजिस्ट्री) दृ खेत, किसान और बोई गई फसल – शामिल हैं। एग्री स्टैक भारत की कृषि से जुड़ी यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत का इशारा करता है। एक ऐसा अध्याय, जो माननीय प्रधानमंत्री के 2047 तक शविकसित भारतत्र के सपने को साकार करने के लक्ष्य के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। खेत वाली रजिस्ट्री में भौगोलिक संदर्भों के आधार पर कृषि भूखंडों का डेटाबेस शामिल होता है। इनमें से प्रत्येक भूखंड को एक अनूठी कृषि आईडी प्रदान की जाती है। दूसरी परत में, प्रत्येक भूमि के मालिक किसान को एक अनूठी फार्म आईडी प्रदान की जा रही है। इस आईडी में स्वामित्व वाली प्रत्येक भूखंड से संबंधित जरूरी जानकारियों के साथ–साथ सह–स्वामित्व के मामले में हिस्सेदारी का उल्लेख भी शामिल है। यह डेटा अधिकार अभिलेख (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) से गतिशील रूप से जुड़ा हुआ है ताकि विरासत, बिक्री आदि के कारण स्वामित्व में हुआ कोई भी बदलाव किसान रजिस्ट्री में अद्यतन हो जाए। तीसरी परत में प्रत्येक भूखंड पर बोई गई फसल का विवरण शामिल होता है। यह विवरण बुवाई पूरी होने के बाद प्रत्येक फसल के मौसम में किए गए डिजिटलध्तकनीक आधारित फसल सर्वेक्षण के जरिए हासिल किया जाता है। केन्द्र सरकार ने विभिन्न समझौता ज्ञापनों के जरिए 35 राज्यों और केन्द्र– शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी की है। इस डिजिटल मिशन को केन्द्र और राज्य के बीच मजबूत सहयोग के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें पूर्ण समावेशन सुनिश्चित करते हुए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। एग्री स्टैक एक संघीय डेटाबेस है जिसका स्वामित्व राज्योंध्केन्द्र–शासित प्रदेशों के पास है, लेकिन केन्द्र सरकार सेवाओं की आपूर्ति और डेटा विश्लेषण के लिए इसका उपयोग कर सकती है। इसका उद्देश्य प्रत्येक किसान के लिए एक सत्यापित डिजिटल पहचान बनाना, उस पहचान को सटीक रूप से मैप किए गए भूखंड से जोड़ना और प्रत्येक मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को दर्ज करना है। यह स्टैक नियमों पर आधारित एवं स्वचालित सेवा वितरण को विभिन्न योजनाओं और भौगोलिक क्षेत्रों में संभव बनाता है। इससे किसानों को बार–बार अपनी पहचान, भूमि स्वामित्व या फसल के विवरण को साबित करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें गोपनीयता और डेटा संरक्षण संबंधी कानूनों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए किसानों से संबंधित जानकारी तक पहुंच एक मजबूत सहमति तंत्र के जरिए होती है। कागजी रिकॉर्ड से डिजिटल आधार तक दशकों तक, कृषि संबंधी प्रशासन कागजी अभिलेखों और मैनुअल सर्वेक्षण पर बहुत अधिक निर्भर रहा। यह अक्सर नागरिकों के लिए उत्पीड़न और भ्रष्टाचार का कारण बनता था। एग्री स्टैक इस पुरानी परंपरा से हटकर एक क्रांतिकारी बदलाव लाता है। किसानों की पहचान का डिजिटलीकरण करके और उन्हें भूमि एवं फसल के आंकड़ों से जोड़कर, यह भारतीय कृषि की एक विश्वसनीय और नई तस्वीर पेश करता है। अब तक 9 करोड़ से अधिक किसान आईडी का सृजन इस सफर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये डिजिटल आईडी एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। इससे किसानों को बार–बार सत्यापन के बिना कई सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलती है और लेन–देन की लागत कम हो जाती है। सरकारी एजेंसियों की दृष्टि से, ये आईडी लाभार्थियों की पहचान में होने वाली त्रुटियों को कम करते हैं और लाभ का सही लाभार्थियों तक पहुंचना सुनिश्चित करने में सहायक साबित होते हैं। हालांकि, यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि एग्री स्टैक की शुरुआत मुख्य रूप से किसानों को विभिन्न योजनाओं के लाभ उठाने के लिए सशक्त बनाने के इरादे से की गई है, लेकिन यह भूमि के रिकॉर्ड या भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र की जगह नहीं लेगा। भले ही अधिकार अभिलेख (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) के साथ इसका जुड़ाव प्रामाणिकता सुनिश्चित करता हो। डिजिटल फसल सर्वेक्षणरू फसल की वास्तविक जानकारी वर्ष 2025–26 में, 24 राज्यों ने 600 से अधिक जिलों में लगभग 30 करोड़ भूखंडों पर मोबाइल उपकरणों, जियोटैगिंग और सैटेलाइट की मदद से डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया। यह सर्वेक्षण पारंपरिक विधियों से हटकर एक महत्वपूर्ण बदलाव है। पारंपरिक विधियां अक्सर धीमी होती थीं और उनमें विसंगतियों या त्रुटियों की गुंजाइश अधिक रहती थी। यह डेटा उपज का अनुमान लगाने, खरीद की योजना बनाने और बाजार से संबंधित पूर्वानुमान लगाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। यह सूखे, बाढ़ या कीटों के कारण फसल पर पड़ने वाले दबाव की शीघ्र पहचान करके आपदा की तैयारी को भी ठोस बनाता है। किसानों के लिए, बेहतर डेटा समय पर एवं फसल–विशेष से जुड़ी सलाह और गड़बड़ होने पर त्वरित सहायता प्रदान करता है। सहयोग एवं समावेशन पर आधारित इकोसिस्टम देश भर में भूमि से जुड़े प्रशासन में मौजूद विविधता को ध्यान में रखते हुए, इस संरचना में स्थानीय जरूरतों के अनुरूप इसे अनुकूलित करने का अंतर्निहित लचीलापन है। साथ ही, अंतरसंचालनीयता सुनिश्चित करने हेतु सामान्य मानकों को बनाए रखा गया है ताकि राज्यों और केंद्रीय प्रणालियों के बीच डेटा का निर्बाध आदान–प्रदान संभव हो सके।

पुलिस मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाश नफीस गिरफ्तार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में कोतवाली पुलिस ने बुधवार देर रात मुठभेड़ के बाद हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर मामलों में वांछित शातिर बदमाश नफीस को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से .315 बोर का देशी तमंचा, कारतूस, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद की है। इस मामले में गुरुवार को जानकारी देते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक गोल्डी गुप्ता ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक विश्वनाथ प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ चहरसू चौराहे पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक बदमाश कटघरा की ओर से तूतीपुर पीपा पुल होते हुए ताड़तला क्षेत्र में किसी वारदात को अंजाम देने आने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तूतीपुर चौराहे पर घेराबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी। कुछ देर बाद एक मोटरसाइकिल सवार युवक आता दिखाई दिया। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर वह भागने लगा। पीछा करने के दौरान उसकी बाइक रेत और लोहे की चद्दर पर फिसलकर गिर गई। इसके बाद बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। गोली प्रभारी निरीक्षक की कनपटी के पास से निकल गई। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान नफीस पुत्र मोहम्मद रफीक निवासी रौजाजमाल खां, थाना कोतवाली, जौनपुर के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, 540 रुपये नकद और एक एंड्रॉइड मोबाइल बरामद हुआ। नफीस पर हत्या के प्रयास, लूट, चोरी और एनडीपीएस एक्ट समेत आठ से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

5 स्कूली वाहन सीज, 11 का चालान

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। बिना परमिट संचालित 5 स्कूली वाहन सीज किए गए हैं, जबकि 11अन्य का चालान किया गया। यह कार्रवाई परिवहन विभाग द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत की गई। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के सख्त निर्देशों के बाद, एआरटीओ (प्रवर्तन) सत्येंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। जांच के दौरान, परमिट, फिटनेस और अन्य आवश्यक दस्तावेज न मिलने पर इन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एआरटीओ (प्रवर्तन) ने स्पष्ट किया कि परमिट, फिटनेस या सुरक्षा उपकरण न होने पर बसों को सीज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस, बस का पीला रंग, स्कूल बस का अंकन और सहायक स्टाफ की उपस्थिति अनिवार्य है। स्कूली वाहन पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, जौनपुर जनपद में कुल 480 वाहन बिना परमिट या समाप्त परमिट के संचालित हो रहे हैं। जनपद के समस्त प्रबंधक, प्रधानाचार्य और वाहन मालिकों को तत्काल परमिट का नवीनीकरण या नया परमिट बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि बिना परमिट के संचालित पाए जाने वाले किसी भी वाहन के खिलाफ चालान या निरुद्ध करने की कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त, जिन विद्यालय प्रबंधन द्वारा अपने वाहनों का परमिट नहीं बनवाया या नवीनीकृत कराया जाता है, उनके विद्यालय की मान्यता समाप्त करने हेतु नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विद्यालय संचालक एवं प्रबंधक की होगी।

यातायात व्यवस्था का एसएसपी ने लिया जायजा, प्रमुख चौराहों और रोडवेज परिसर का किया निरीक्षण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जनपद में सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर कुँवर अनुपम सिंह ने नगर क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख चौराहों एवं संवेदनशील स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण, पार्किंग और आमजन की सुविधाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने जेसीस चौराहा, पॉलीटेक्निक चौराहा, वाजिदपुर तिराहा सहित अन्य प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया। उन्होंने सड़क पर अव्यवस्थित तरीके से खड़े वाहनों, अवैध पार्किंग और यातायात बाधित करने वाले अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही यातायात पुलिस और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को चौराहों पर यातायात संचालन और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निर्देशित किया। एसएसपी ने विशेष रूप से स्कूल, बाजार और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा, ताकि आमजन को जाम की समस्या से राहत मिल सके। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने रोडवेज परिसर का भी दौरा किया, जहां रोडवेज के एआरएम के साथ सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस दौरान यात्रियों की सुविधा, बसों के आवागमन, पार्किंग व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। एसएसपी ने रोडवेज परिसर में अवैध वाहन पार्किंग और अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए समन्वय बनाकर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनपद में सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है और आमजन को सुरक्षित एवं सुगम यातायात उपलब्ध कराने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष श्रीवास्तव सहायक पुलिस अधीक्षक गोल्डी गुप्ता क्षेत्राधिकारी नगर देवेश कुमार सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

जौनपुर में बिना परमिट दौड़ रहीं 400 से अधिक बसें, बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा :अजीत सिंह

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में बिना परमिट और बिना फिटनेस के दौड़ रही प्राइवेट एवं स्कूली बसें लोगों की जान पर भारी पड़ रही हैं। आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं के बावजूद परिवहन विभाग की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। विभागीय दावों के बावजूद जिले में लगभग 400 से अधिक बसें बिना पंजीकरण और फिटनेस के सड़कों पर फर्राटा भर रही हैं, जिससे आम जनता और स्कूली बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। परिवहन विभाग लगातार फिटनेस अभियान चलाने और स्कूल बसों की जांच का दावा करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बिना फिटनेस और परमिट वाले वाहन खुलेआम सड़कों पर संचालित हो रहे हैं। इससे स्कूल संचालकों और प्राइवेट वाहन मालिकों के हौसले बुलंद हैं, जबकि दुर्घटनाओं का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस मामले में उप संभागीय परिवहन अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि जौनपुर एआरटीओ कार्यालय में अब फिटनेस सेंटर शुरू कर दिया गया है। पहले वाहनों की फिटनेस वाराणसी में होती थी, जिससे वाहन संचालकों को परेशानी होती थी। अब जिले में ही फिटनेस सुविधा उपलब्ध करा दी गई है ताकि वाहन मालिक आसानी से अपने वाहनों की जांच करा सकें। उन्होंने बताया कि सभी स्कूल संचालकों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने वाहनों की फिटनेस, पंजीकरण और बीमा समेत सभी दस्तावेज दुरुस्त कर लें। जिन स्कूल वाहनों की फिटनेस फेल है, उन्हें तत्काल आरटीओ कार्यालय में प्रस्तुत कर फिटनेस करवाने को कहा गया है। एआरटीओ ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते स्कूल वाहनों की फिटनेस नहीं कराई गई तो उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा और दोबारा बहाल नहीं किया जाएगा। साथ ही संबंधित स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए शासन को भी पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

तीन साल बाद मिली गुमशुदा बालिका, एएचटीयू की सतर्कता से सुरक्षित बरामद

लखनऊ, (संवाददाता)। थाना पीजीआई क्षेत्र से वर्ष 2023 में लापता हुई 14 वर्षीय बालिका को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। यह सफलता क्राइम ब्रांच के अंतर्गत कार्यरत एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (।भ्ज्न्) की सतत निगरानी और समन्वित प्रयासों से मिली है। प्रकरण के अनुसार 13 अप्रैल 2023 को वादिनी द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के गुमशुदा होने पर थाना पीजीआई में मु0अ0सं0–261ध्2023 धारा 363 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। प्रारंभिक विवेचना थाना पीजीआई द्वारा की जा रही थी, जिसे बाद में संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय के आदेश पर एएचटीयू को स्थानांतरित कर दिया गया।वर्तमान में मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सत्यपाल सिंह द्वारा की जा रही थी। प्रभारी निरीक्षक दशरथ सिंह के नेतृत्व में टीम ने विभिन्न बाल आश्रय गृहों से समन्वय स्थापित करते हुए बालिका की तलाश जारी रखी। इसी क्रम में 4 मई 2026 को सूचना मिली कि एक बालिका, जिसने अपना नाम बदल रखा है, पहले राजकीय बालगृह सिंधीखेड़ा में रह चुकी है और वर्तमान में कुर्सी रोड स्थित स्नेहालय बालिका गृह में निवास कर रही है।सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बालिका की पहचान सुनिश्चित की। पूछताछ में बालिका ने बताया कि घर में माता–पिता के बीच होने वाले विवाद से परेशान होकर वह घर छोड़कर चली गई थी और पहचान छिपाने के लिए नाम बदलकर बालिका गृह में रह रही थी।पुलिस ने विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए बालिका को सकुशल बरामद कर लिया है। आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।बरामदगी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक दशरथ सिंह, उपनिरीक्षक सत्यपाल सिंह, आरक्षी संदीप कुमार यादव और महिला आरक्षी पूजा देवी शामिल रहे।पुलिस ने बताया कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा गुमशुदा बच्चों की तलाश और उनकी सुरक्षा के लिए लगातार 24 घंटे निगरानी और कार्रवाई की जा रही है, ताकि कोई भी नाबालिग मानव तस्करी या शोषण का शिकार न हो सके।

मऊ में शिक्षामित्र सम्मान समारोह आयोजित, मानदेय वितरण के साथ सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई

लखनऊ, (संवाददाता)। नगर पालिका कम्युनिटी हॉल, मऊ में शिक्षामित्र सम्मान समारोह एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन ए.के. शर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जनपद भर से बड़ी संख्या में शिक्षामित्रों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की।कार्यक्रम का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ से आयोजित प्रदेशव्यापी कार्यक्रम के सजीव प्रसारण के साथ हुआ। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने शिक्षामित्रों के धैर्य, समर्पण और शिक्षा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा से जुड़े कर्मियों के सम्मान और आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि सरकार "सबका साथ, सबका विकास" के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने शिक्षामित्रों को प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की मजबूत कड़ी बताते हुए कहा कि यह कार्यक्रम केवल मानदेय वितरण नहीं, बल्कि उनके प्रति सरकार के सम्मान और विश्वास का प्रतीक है।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, एक की मौत

लखनऊ, (संवाददाता)। अंबेडकरनगर जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे (किमी 82.200) पर मंगलवार आधी रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। आजमगढ़ के कप्तानगंज क्षेत्र से एक तेरही कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे लोगों की बोलेरो खराब हो गई थी। खराब वाहन को दूसरी बोलेरो से टोचन (खींचना) किया जा रहा था, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में आजमगढ़ निवासी प्रिंस यादव, दीपक, साजिद और छोटेलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपीडा टीम और जैतपुर थाना अध्यक्ष धीरेंद्र आजाद ने तत्काल घायलों को सीएचसी जलालपुर पहुंचाया, जहाँ डॉक्टरों ने छोटेलाल को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों का उपचार जारी है। घटना की सूचना पर एसडीएम राहुल गुप्ता और क्षेत्राधिकारी अनूप कुमार सिंह ने भी मौके का मुआयना किया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू कराया है।

यूपीपीसीएल ने न्यूनतम मजदूरी दरों में किया संशोधन

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करते हुए नई दरें लागू कर दी हैं। यह संशोधन 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जाएगा। निगम ने यह निर्णय श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुपालन में लिया है, जिससे प्रदेश के श्रमिकों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिल सके।जारी आदेश के अनुसार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी में परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) जोड़कर नई दरें निर्धारित की गई हैं।

रक्त के अभाव में नहीं जाने देंगे किसी बेसहारा व्यक्तियों की जान-घनश्याम वर्मा भाकियू महासचिव

(डीकेयू लाइव ब्यूरो चीफ रिपोर्टर) सुरेंद्र कुमार।

अयोध्यारूभाकियू महासचिव घनश्याम वर्मा के जन्मदिन पर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने जिला चिकित्सालय में स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान करके बेसहारा लोगों की जान बचाने का संकल्प लिया

कार्यक्रम में गोसाईगंज विधायक अभय सिंह पहुंचकर भाकियू महासचिव घनश्याम वर्मा को साल ओढाकर सम्मानित करते हुए जन्मदिन की बधाई दिया और केक काटा तथा रक्तदानियों का हौसला अफजाई किया। गोसाईगंज विधायक भाकियू महासचिव घनश्याम वर्मा की समाज सेवा,संघर्ष की सराहना करते हुए रक्तदान को पुनीत कार्य बताया। भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा रक्तदान करके बेसहारा लोगों तथा सैनिकों हेतु रक्त की व्यवस्था करना सराहनीय कार्य है।

भाकियू महासचिव घनश्याम वर्मा ने कहा कि रक्त के अभाव में किसी भी बेसहारा व्यक्ति की जान नहीं जाने देंगे 5 मई के अतिरिक्त भी जब भी किसी भी बेसहारा व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े मुझसे संपर्क करें।

रंजीत कोरी ,राकेश कुमार पाल,रविंद्र कुमार मौर्य,अवधेश कुमार उर्फ राजेश वर्मा, भागीरथी वर्मा, घनश्याम वर्मा ,जगदीश प्रसाद यादव, सूर्यनाथ वर्मा ,राहुल वर्मा, उर्मिला निषाद,विपुल वर्मा, संतोष वर्मा, अमर कुमार पंकज कुमार, विवेक पटेल, विकास वर्मा,सरोज वर्मा ने रक्तदान किया

किसान नेता फरीद अहमद,शंकरपाल पांडे,रवि शंकर पांडे मंशाराम वर्मा,सिद्धू भारती, रामबचन भारती, अमरजीत मौर्य, सहित कई दर्जन कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे।

मीरगंज-पवारा पुलिस मुठभेड़ में शातिर अपराधी घायल गिरफ्तार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मीरगंज और थाना पवारा पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार रात मुठभेड़ के दौरान एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सीएचसी मछलीशहर भेजा गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है।इस मामले में गुरुवार को जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी मछलीशहर प्रतिमा वर्मा ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुँवर अनुपम सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम कुंवरपुर तिराहे पर चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि एक अपराधी अवैध असलहे के साथ भागने की फिराक में है।

सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की। इसी दौरान चितांव की ओर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर उसने बाइक मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाइक फिसलने से वह गिर गया। पुलिस के पकड़ने का प्रयास करने पर आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी घायल हो गया।

पूछताछ में आरोपी की पहचान मो. उमर पुत्र सुहेल अहमद निवासी ग्राम चोरसण्ड, थाना गौराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर के रूप में हुई। पुलिस ने उसके पास से एक देशी तमंचा .315 बोर, कारतूस बाइक बरामद किया है। आरोपी पर हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम समेत कई गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर रुस्तम घायल, तमंचा और बाइक बरामद

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बरसठी और रामपुर पुलिस की संयुक्त टीम को बुधवार देर रात बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस मुठभेड़ में शातिर हिस्ट्रीशीटर एवं लुटेरा रुस्तम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देश पर जिलेभर में संदिग्ध अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था। गुरुवार को जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि बरसठी थाना प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश यादव और रामपुर थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार अपनी टीम के साथ परियत तिराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बिना नंबर प्लेट की काले रंग की सुपर स्प्लेंडर बाइक पर सवार दो संदिग्ध युवक आलमगंज की ओर से आ रहे हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने महमूदपुर बैरी पट्टी तिराहे पर घेराबंदी कर दी। देर रात जैसे ही संदिग्ध बाइक मौके पर पहुंची, पुलिस ने रुकने का इशारा किया। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की। मुठभेड़ के दौरान बाइक चला रहा बदमाश गोली लगने से घायल होकर गिर पड़ा, जबकि उसका साथी झाड़ियों के रास्ते फरार हो गया। घायल बदमाश की पहचान रुस्तम पुत्र मुस्लिम निवासी सहाबुद्दीनपुर, थाना गौराबादशाहपुर जौनपुर के रूप में हुई। पुलिस ने उसके कब्जे से एक 32 बोर का देशी तमंचा, कारतूस तथा बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की है। पुलिस जांच में सामने आया कि रुस्तम पर जौनपुर और आजमगढ़ के विभिन्न थानों में लूट, चोरी, गैंगस्टर एक्ट, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत एक दर्जन से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।

जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने कार्यभार संभालते दो उपजिलाधिकारियों के कार्यक्षेत्र में किया बदलाव

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर के जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने कार्यभार संभालने के तुरंत बाद प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव किया है। गुरुवार को उन्होंने दो उपजिलाधिकारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया। डीएम के जारी आदेश के अनुसार, बदलापुर की उपजिलाधिकारी योगिता सिंह को मछलीशहर का एसडीएम नियुक्त किया गया है। वहीं, मछलीशहर के उपजिलाधिकारी न्यायिक शिव प्रताप को बदलापुर का एसडीएम बनाया गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह बदलाव कार्यप्रणाली में गति लाने और जनसेवा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है। नवागत जिलाधिकारी के इस निर्णय से क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासनिक सक्रियता बढ़ने की उम्मीद है। कार्यभार संभालने के बाद जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले की कानून–व्यवस्था, विकास योजनाओं और राजस्व संबंधी मामलों की समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान ही प्रशासन की असली पहचान है और इसके लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करना होगा।

'खेत तालाब योजना से सिंचाई की टेंशन होगी खत्म और कमाई होगी डबल-निधि राठौर'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' भूमि संरक्षण अधिकारी डा0 निधि राठौर ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में जल संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए संचालित खेत तालाब योजना को योगी सरकार नए वित्तीय वर्ष में और अधिक मजबूती से आगे बढ़ा रही है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप (प्रति बूंद अधिक फसल) के संकल्प को हर खेत तक पहुँचाया जाए। इसी कड़ी में, जनपद हरदोई के लिए वर्ष 2026–27 के लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं, जिसके तहत पात्र किसानों को तालाब निर्माण पर लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिससे न केवल सिंचाई की समस्या हल हुई है, बल्कि किसानों ने मछली पालन और जलीय खेती के जरिए अपनी कमाई के अतिरिक्त स्रोत भी विकसित किए हैं।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत संचालित इस योजना में किसानों को अपने खेत में तालाब बनाने के लिए लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। एक मानक लघु तालाब (22 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा) बनाने की कुल लागत 1.05 लाख रुपये तय की गई है। इसमें सरकार की ओर से 52,500 रुपये की आर्थिक मदद सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी। खेत तालाब योजना किसानों के लिए खुशहाली का नया द्वार है। इससे न केवल वर्षा जल का संचयन होगा और भूगर्भजल स्तर में सुधार आएगा, बल्कि किसान इस तालाब में मछली पालन, सिंघाड़ा और मखाना जैसी जलीय खेती करके अतिरिक्त मुनाफा भी कमा सकते हैं। यह योजना गाँवों में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और किसानों को सिंचाई के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

भूमि संरक्षण अधिकारी ने कहा कि सरकार केवल तालाब बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस पानी के सही इस्तेमाल के लिए भी भारी छूट दे रही है। तालाब के साथ सिंचाई के लिए ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम (टपक सिंचाई) लगाना अनिवार्य है, जिस पर सरकार 80 से 90 प्रतिशत तक की भारी सब्सिडी दे रही है। इतना ही नहीं, पानी निकालने के लिए पंपसेट खरीदने पर भी 50 प्रतिशत (अधिकतम 15 हजार रुपये) की मदद दी जाएगी। वर्ष 2026–27 के लिए हरदोई को 27 तालाबों का लक्ष्य मिला है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 25 और अनुसूचित जाति के लिए 02 तालाबों का कोटा तय किया गया है और यह अनुदान दो चरणों में मिलेगा पहली किस्त तालाब की खुदाई का काम पूरा होने पर व दूसरी किस्त पानी आने का रास्ता (इनलेट) और डिस्चेल बोर्ड लगने के बाद।

जरूरी दस्तावेज आवेदन के लिए किसान की फार्मर रजिस्ट्री होना अनिवार्य है, टोकन मनी ऑनलाइन आवेदन के साथ 1000 रुपये की टोकन राशि जमा करनी होगी, वेबसाइट इच्छुक किसान कृषि विभाग के पोर्टल griculture.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते है, समय सीमा बुकिंग के 15 दिन के भीतर सत्यापन होगा और 30 दिन के भीतर तालाब तैयार करना होगा, अधिक जानकारी के लिए किसान भूमि संरक्षण अधिकारी द्वितीय हरदोई कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 8840584974 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

दलित युवक से मारपीट और अवैध वसूली का आरोप, पीड़ित ने मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। रुदौली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दलसराय से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है गांव निवासी निर्धन दलित युवक मनोज गौतम ने कोतवाली में तैनात सिपाही अजीत यादव पर चोरी के शक में बेरहमी से मारपीट करने अवैध धन उगाही करने और परिवार को धमकाने का आरोप लगाया है घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है वहीं पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है पीड़ित मनोज गौतम का आरोप है कि पुलिस उसे पूछताछ के नाम पर थाने ले गई जहां उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया मनोज का कहना है कि सिपाही ने उसे लगातार पीटा और घर की महिलाओं से पैसे मंगवाने का दबाव बनाया आरोप है कि परिवार द्वारा पैसे देने के बावजूद भी उसके साथ मारपीट जारी रही जिससे उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पड़ गए पीड़ित का यह भी आरोप है कि मारपीट के बाद पुलिस ने मामले को दबाने के लिए उसका शांति भंग में चालान कर दिया बाद में जमानत पर रिहा होने के बाद मनोज गौतम ने मीडिया के सामने अपनी आपबीती सुनाई और शरीर पर मौजूद चोटों के निशान दिखाए इस दौरान बनाया गया वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है लोगो का कहना है कि यदि आरोप सही हैं तो यह बेहद गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए दलित युवक के साथ कथित उत्पीड़न और अवैध वसूली के आरोपों ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्य से मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए फिलहाल मामले को लेकर पुलिस विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब सभी की निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई हैं

चीनी उद्योग व गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने किया रामलला का दर्शन-पूजन

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। चीनी उद्योग व गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने रामलला का दर्शन–पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता मौजूदा शासन से पूरी तरह ऊब चुकी थी।कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह का शासन चल रहा था।वैसा शासन अंग्रेजों के समय में भी नहीं था।आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में गाय और बैलों की हत्या कर उन्हें बांग्लादेश भेजा जाता था।ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जनता और गौमाता की "हाय" लगी है।सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक हैं।उन्होंने कहा कि अगर ऐसी घटनाओं के बावजूद सरकार नहीं बदलती तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी।जनगणना को जरूरी बताते हुए कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष कार्य और अलग व्यवस्था होनी चाहिए।बिहार में अति पिछड़ों को अलग आरक्षण मिलने का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भी इस मुद्दे पर विचार होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने पर कहा कि एक साल पहले पाकिस्तान का "दिमाग ठीक किया गया था" और अगर फिर बदमाशी होगी तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा।

ओवरब्रिज पर ब्रेकर न होने से हादसों का खतरा,स्थानीय लोगों में आक्रोश

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।क्षेत्र के दर्शन नगर चौराहे के पास फैजाबाद से अकबरपुर जाने वाली रोड पर बने ओवरब्रिज पर ब्रेकर न होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ओवरब्रिज पर वाहनों की रफ्तार काफी तेज रहती है, लेकिन सड़क पर कहीं भी ब्रेकर या गति नियंत्रित करने की व्यवस्था नहीं की गई है।ब्रेकर न होने के

कारण वाहन चालक तेज गति से गुजरते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना लगातार बनी रहती है। कई बार छोटे–बड़े हादसे भी हो चुके हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है।इस संबंध मे स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि ओवरब्रिज पर जल्द से जल्द ब्रेकर, संकेतक बोर्ड एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और लोगों की जान सुरक्षित रह सके। व्यापार मंडल अध्यक्ष राममिलन विश्वकर्मा ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि हाईवे पर जहां–जहां बाजार क्षेत्र पड़ते हैं, वहां ब्रेकर बनाया जाना बेहद जरूरी है, ताकि वाहन नियंत्रित गति में चलें और हादसों को रोका जा सके।

सरयू नदी में नहाने के लिए उतरे चार युवकों मे से तीन लापता,जल पुलिस ने एक को बचाया

अयोध्या। गुरुवार को सुबह सात बजे सरयू नदी के लक्ष्मण घाट पर नहाने के लिए चार युवक अचानक डूबने लगे जिनमें से एक युवक को जल पुलिस ने बचाया जबकि तीन युवक अभी भी लापता है।बताते चले कि बस्ती जिले के निवासी अभिषेक कुमार, सुजल और राज गुप्ता गये।जबकि किशन सोनी बाहर ही सरयू नदी के बैठा रहा।किशन ने बताया कि मेरे दोस्त नहाते हुए घाट से दूर जा रहे थे।मैंने उन्हें रोका।मगर वह नहीं माने।तभी अचानक सभी दोस्त डूबने लगे।जब अपने दोस्तों को जब वह डूबते हुए देखा तो उसने शोर मचाया। शोर सुनकर घाट पर मौजूद जल पुलिस व गोताखोर सरयू नदी में कूद गए और डूब रहे उनके दोस्तों को ढूंढने लगे।इनमें से एक को घाट पर तैनात जल पुलिस ने बचा लिया।जबकि 3 लड़के नदी में डूब गए।जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें तीनों की तलाश कर रही हैं।10 से अधिक गोताखोर भी लगाए गए हैं।डूबने वाले तीनों लड़के बस्ती के रहने वाले हैं। ये लोग अपने दोस्त किशन का बर्थडे मनाने अयोध्या पहुंचे थे। घटना लक्ष्मण घाट की है।इस संबंध में एसपी ग्रामीण चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि तीनों युवकों की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम सुबह 7 बजे से सर्च ऑपरेशन चला रही है।दोपहर दो बजे तक 7 घंटा बीत चुका है।अब तक तीनों का कोई सुराग नहीं मिला है।तीनों की तलाश के लिए एसडीआरएफ और जल पुलिस की 4 टीम दो किलोमीटर की तलाश में जुटी है।वही मॉनिटरिंग के लिए मौके पर एडीएम अरविंद कुमार, कोतवाली प्रभारी पंकज कुमार सिंह सहित प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है।घटना की जानकारी के बाद युवकों के परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गये।परिवार की महिलाओं का रो–रोकर बुरा हाल है।बताते चले कि बस्ती जिले के रहने वाले किशन सोनी का गुरुवार को बर्थडे है।वह अपने दोस्तों अभिषेक कुमार, सुजल और राज गुप्ता के साथ अयोध्या पहुंचा था। गुरुवार सुबह सभी दोस्त लक्ष्मण घाट पर स्नान करने बस्ती के रहने वाले राजीव गुप्ता का कहना है कि उनका बेटा राज रात में चुपके से अयोध्या आ गया।सुबह घर में 5 बजे नहीं देखा तो दूसरे पुत्र ने बताया कि राज अपने दोस्त के बर्थ डे के लिए अयोध्या गया है।सुबह फोन पर बात था कि वह शाम 6 बजे तक आ जाएंगे।राज के डूबने की सूचना उनको सुबह 8 बजे मिली।डूबने की जानकारी मिलने पर वह यहां आए हैं।बताते चले कि किशन सोनी के पिता किराना की दुकान करते हैं।उसके घर से अभी कोई नहीं आया।डूबे हुए युवक सुजल की मामी पिंकी गुप्ता ने बताया कि सुजल डांसर है।वह घर से बताकर आया था कि अयोध्या जा रहे हैं।उसके पिता भी किराना की दुकान करते हैं।इसके अलावा अमरोहा जिले के दो लड़के सरयू में डूब गए।दोनों को जल पुलिस ने बचा लिया।जल पुलिस के अरक्षी नित्यानंद यादव ने बताया कि घटना सुबह करीब 6 बजे हुई।इनमें अमरोहा के गांव दिदौली के रहने वाले अरुण और उसके दोस्त को बचा लिया गया।

पूर्व मंत्री अब्बास अली `जैदी रुश्दी' मियां का एक और बड़ा प्रयास लाया रंग दूसरा भी शव विदेश से आया

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। दुबई में काम कर रहे मिल्कीपुर विधानसभा के ग्राम सभा मेहंदी निवासी गंगादीन लोधी पुत्र सोहन लाल लोधी की मौत के बाद से परिवार गहरे सदमे में है। करीब एक माह पहले हुई इस घटना ने पूरे घर को तोड़ कर रख दिया था। परिजनों की बस एक ही तमन्ना थी कृ बेटे का पार्थिव शरीर किसी तरह वतन लौट आए, ताकि अंतिम दर्शन कर सकें।इस दुख की घड़ी में जानकारी पाकर पीड़ित के घर पहुंचे सांसद अवधेश प्रसाद ने पोंछे पीड़िता के आंसू व आश्वासन दिया कि बेटे का शव घर आयेगा वहीं सहारा बनकर पूर्व मंत्री अब्बास अली जैदी सामनज आये।उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि हर हाल में गंगादीन का शव भारत लाया जाएगा। पिछले करीब 30 दिनों से लगातार प्रयास, दुबई में कागजी प्रक्रिया और अधिकारियों से संपर्क के बाद आखिरकार शव भारत लाने की प्रक्रिया पूरी हो सकी।पूर्व मंत्री रुश्दी मियां स्वयं पार्थिव शरीर लेने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, ताकि शव को रिसीव कर सकें और उसे सकुशल परिजनों तक पहुंचाया जा सके। गांव में लोग टकटकी लगाए इंतजार कर रहे थे कि कब गंगादीन अपने घर पहुंचे और परिवार उसे अंतिम विदाई दे सके।गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब रुश्दी मियां ने इस तरह किसी पीड़ित परिवार की मदद की हो। आठ से दस दिन पहले ही उन्होंने रूदौली विधानसभा के परसन पुरवा मजरे बारी निवासी सुरेंद्र लोधी का पार्थिव शरीर भी सऊदी अरब से भारत मंगवाकर परिजनों तक पहुंचाया था। उस समय भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रयास कर कागजी कार्यवाही पूरी कराई थी, जिससे शोकाकुल परिवार अपने बेटे का अंतिम संस्कार अपने हाथों कर सका।लगातार इस तरह की मानवीय पहल से क्षेत्र में उनकी संवेदनशील छवि और मजबूत हुई है। लोग कह रहे हैं कि आज के दौर में जहां अक्सर लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं, वहीं रुश्दी मियां अपने कार्यों से यह साबित कर रहे हैं कि वह हर पीड़ित के साथ एक जिम्मेदार भाई की तरह खड़े हैं।पूर्व विधायक रुश्दी जी अपने साथियों के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे हंसराज लोधी, कमलेश यादव, बाबा फरीद अहमद, सुरजीत चौहान, मैकुराम लोधी, रामफेर लोधी, भैया राम लोधी, अनिल लोधी, अमरेश निषाद मौजूद रहे।

आपरेशन सिंदूर के जरिये भारतीय सेना ने आतंकी व उनके आकाओं को चटाया धूल – डिप्टी सीएम

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक अयोध्या पहुंचे।महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उनका भव्य कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत हुआ।मीडिया से बातचीत में उन्होंने पुलवामा हमले के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि "हुतात्माओं को नमन करते हैं, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों और उनके आकाओं को धूल चटाने का काम किया।" उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को पूरे देश के लिए गौरव का क्षण बताया और भारतीय सेना की सराहना की।पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए।बृजेश पाठक ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और जनता बदलाव चाहती है।उन्होंने दावा किया कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने की प्रक्रिया चल रही है।समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा और तृणमूल कांग्रेस एक जैसी राजनीति करती हैं।डिप्टी सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार, अराजकता और "वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया" के दौर को नहीं भूली है।उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 2017 का इतिहास दोहराते हुए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, साथ ही अयोध्या दौरे में स्वास्थ्य विभाग की बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा भी करेंगे।

आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर्मचारियों की सेवा एवं अवकाश नियमावली बने – आलोक तिवारी

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग योजना के अंतर्गत की जाती है जिसके अंतर्गत कार्य करने वालों कर्मचारी साथियों की कोई सेवा नियमावली नहीं है।ना ही अवकाश नियमावली है।जिससे कर्मचारियों का शोषण किया जाता है।संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य महोदय का कहना है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए कोई अवकाश नियमावली नहीं है मजबूरन हमें काम लेना पड़ता है प्रधानाचार्य द्वारा उनकी उपस्थिति प्रमाणित की जाती है उसी के आधार पर वेतन संबंधित फर्म देती है

यदि कोई नियमावली बन जाए तो उसके अनुसार कार्य लिया जाएगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री आलोक तिवारी ने शासन प्रशासनविभागीय अधिकारियों से मांग की है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा नियमावली बने एवं उनके अवकाश की भी नियमावली बने जिससे कर्मचारियों का उत्पीड़न से बचाया जा सके जल्द ही जिला संगठन इस समस्या के निदान हेतु शिक्षक विधायक फैजाबाद गोरखपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी से वार्ता करेगा।

महिला थानाध्यक्ष की सूझबूझ से पति पत्नी एक बार फिर साथ रहने को हुए सहमत

अयोध्या। महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला व महिला पुलिस की सूझबूझ से एक परिवार टूटने से बचा।मामूली विवाद के चलते काफी दिनों से पति पत्नी एक दूसरे से दूर रह रहे थे जिसका असर छोटे–छोटे बच्चों पर पड़ रहा था।महिला थानाध्यक्ष तथा उनकी टीम द्वारा किए गए काउंसलिंग के चलते गुरुवार को एक बार फिर आपस में रहने के लिए राजी हुए जिससे इन दोनों के छोटे–छोटे बच्चों का भविष्य भी खराब होने से बचा।इस संबंध में महिला थाना अध्यक्ष आशा शुक्ला ने बताया अमरीन खान की शादी दानिश निवासी बच्चू का पुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर के साथ हुई थी।जो काफी दिनों से मनमुटाव के चलते एक दूसरे से अलग थे लेकिन आज गुरुवार को एक बार फिर एक हो गये।

मछली बनाने से इंकार करने पर पत्नी ने पति को पीटा

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।जिले के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में पति–पत्नी के बीच हुआ विवाद हिंसक रूप ले बैठा।मामूली कहासुनी के बाद पत्नी ने पति पर लाठी–डंडों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में युवक किसी तरह थाने पहुंचा और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी।घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है।बताया जा रहा है कि बीकापुर क्षेत्र के परोमा मठिया गांव निवासी रायसिंह बाजार से मछली खरीदकर घर लौटे थे। घर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी कुमकुम सिंह से मछली बनाने के लिए कहा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया।आरोप है कि गुस्से में आई पत्नी ने लाठी–डंडे उठाकर रायसिंह पर हमला कर दिया। हमले में युवक को गंभीर चोटें आईं और उसके शरीर से खून बहने लगा। घायल युवक किसी तरह खुद को बचाते हुए बीकापुर कोतवाली पहुंचा, जहां उसने पुलिस को पूरी घटना बताई। पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए भेज दिया है। मामले की तहरीर मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एजेंसी पर हंगामा, कर्मचारियों से नोकझोंक– पुलिस के समझाने के बाद बंटे सिलिंडर

गोरखपुर, (संवाददाता)। सूबा बाजार स्थित भारत गैस एजेंसी पर मंगलवार सुबह उपभोक्ताओं ने हंगामा किया। इस दौरान कर्मचारियों से नोकझोंक भी हुई। भोर से ही लाइन में लगे उपभोक्ता वाहन से सिलिंडर पहुंचने पर धक्का–मुक्की करने लगे। इस दौरान अफरातफरी का माहौल रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को समझाकर मामला शांत कराया। उसके बाद वितरण शुरू हो सका। हालांकि 80 लोगों को ही सिलिंडर मिल सका। सूबा बाजार स्थित भारत गैस एजेंसी पर मंगलवार भोर से ही बड़ी संख्या में उपभोक्ता एजेंसी पर पहुंच गए थे। जैसे ही गैस सिलिंडर से भरा वाहन पहुंचा, भीड़ बढ़ने से धक्का–मुक्की और कर्मचारियों से नोकझोंक शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ते देख एजेंसीकर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया और लाइन व्यवस्थित कराई। इसके बाद वितरण कार्य शुरू हो सका। लाइन में लगे समीर अली, बेगम निशा, गुड्डू, सुरेंद्र, मंजू, विनोद, अनिल और अमन समेत करीब 80 उपभोक्ताओं को गैस सिलिंडर दिया गया। कई लोगों को बिना सिलिंडर लिए ही लौटना पड़ा। जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि क्षेत्र में बैकलॉग के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है। लगभग 5000 घरेलू गैस सिलिंडरों की कमी बनी हुई है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। फिलहाल बुकिंग के बाद डीएसी नंबर के आधार पर ही सिलिंडर दिए जा रहे हैं। सहालग और विवाह सीजन के चलते मांग में तेजी आई है। ऐसे में प्रतिदिन 25 से 30 हजार सिलिंडरों के वितरण का लक्ष्य तय किया गया है, ताकि जल्द ही स्थिति सामान्य की जा सके। शादी–विवाह के सीजन में कॉमर्शियल गैस सिलिंडरों की बढ़ती मांग ने व्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है। हालात यह है कि गैस सिलिंडर पाने के लिए करीब 5100 लोगों ने आवेदन किया लेकिन कई उपभोक्ताओं को समय पर सिलिंडर नहीं मिल पा रहा है। गैस एजेंसियों पर बढ़ते दबाव के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

जमीन के विवाद में दो भाजपा विधायकों में आरोप–प्रत्यारोप

उन्नाव, (संवाददाता)। मोहान विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक बृजेश रावत के छोटे भाई राजेश रावत ने सदर विधायक पंकज गुप्ता और उनकी बहन दीप्ति गुप्ता पर पैतृक जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। राजेश ने सदर कोतवाली और एसडीएम को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। विवाद लखनऊ–कानपुर हाईवे पर नवीन मंडी के पास स्थित जमीन को लेकर है। मोहान विधायक इसे अपनी पैतृक जमीन का हिस्सा बता रहे हैं। वहीं सदर विधायक ने अधिकारियों से जांच करने जिसकी जमीन हो उसे कब्जा देने की मांग की है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी मे. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार-पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।